हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

हर खबर पर पैनी नजर

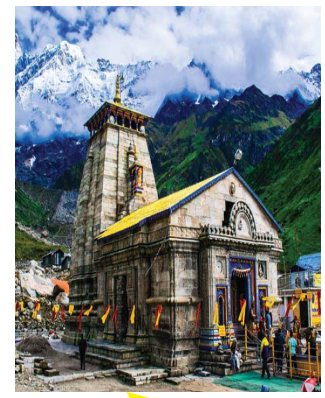

वर्ष:5 अंक:32 पृष्ठ:08 मुल्य:1 रूपये pathpravah.com हरिद्वार, शुक्रवार, 06 फरवरी 2026

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का सामाजिक सुरक्षा पर फोकस, 9.47 लाख लाभार्थियों को पेंशन

पथ प्रवाह, देहरादून।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पात्रता परीक्षण, सत्यापन एवं भुगतान प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ व त्वरित करने के निर्देश समाज कल्याण विभाग को दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक निर्बाध रूप से पहुंचे।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मुख्यमंत्री आवास से जनवरी 2026 माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि का वन-क्लिक प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भुगतान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित, पारदर्शी और संवेदनशील शासन व्यवस्था ही सुशासन की पहचान है, जिसे राज्य सरकार निरंतर सशक्त कर रही है।

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में जनवरी 2026 में राज्य के 9,47,345 पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का

लाभ दिया गया। इसके तहत कुल 141 करोड़ 66 लाख 51 हजार की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से खातों में हस्तांतरित की गई, जिसमें नियमित पेंशन के साथ एरियर भुगतान भी शामिल रहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, किसान, निराश्रित एवं जरूरतमंद वर्गों के लिए पेंशन योजनाएं केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन का आधार हैं। DBT और वन-क्लिक भुगतान प्रणाली से न केवल भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है, बल्कि लाभार्थियों को बिना किसी कार्यालयी प्रक्रिया के सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि 01 दिसंबर 2025 से 03 फरवरी 2026 के बीच 15,784 नए लाभार्थियों को पेंशन योजनाओं से जोड़ा गया, वहीं 1,523 अपात्र नामों को पोर्टल से हटाकर पारदर्शिता सुनिश्चित की गई। डिजिटल पेंशन पोर्टल और स्वतः पात्रता पहचान प्रणाली से अब स्वीकृति प्रक्रिया अधिक सरल और मानवीय हुई है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार का संकल्प है कि सुशासन और तकनीक के माध्यम से योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इस अवसर पर अपर सचिव संदीप तिवारी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

पीएम मोदी ने राज्यसभा में संबोधन के दौरान ली चुटकी और बोले- खड़गे जी बैठकर करें नारेबाजी, उनकी उम्र का ख्याल...

नई दिल्ली। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब के दौरान गुरुवार को राज्यसभा में माहौल काफी गरम रहा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही संबोधन शुरू किया विपक्षी सदस्यों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। इसी हंगामे के बीच पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर हल्के-फुल्के अंदाज में चुटकी ली, जिस पर सत्ता पक्ष में ठहाके गूंज उठे। जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सांसदों ने सदन से वाकआउट किया, जिस पर पीएम मोदी ने फिर चुटकी ली। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आदरणीय सभापति जी, मेरी एक प्रार्थना है। आदरणीय खड़गे जी की उम्र को देखते हुए मेरा अनुरोध है कि वे बैठकर नारेबाजी करें। खड़े होकर नारे लगाने का काम नौजवानों के लिए छोड़ दें। उन्होंने यह भी कहा कि बैठ कर नारे लगाने से खड़गे जी को कष्ट नहीं होगा और विपक्ष के युवा सदस्य खड़े होकर नारे लगा सकते हैं।

पीएम मोदी के इस बयान के बाद सदन में शोर और बढ़ गया। विपक्षी सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे, जबकि प्रधानमंत्री बिना रुके अपना जवाब देते रहे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य साफ है– हमें न रुकना है, न पीछे मुड़कर देखना है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश की आर्थिक स्थिति और वैश्विक छवि का जिक्र करते हुए कहा कि भारत आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया का भारत के प्रति भरोसा बढ़ा है और आज वैश्विक मंच पर भारत को गंभीरता से सुना जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि देश तेज विकास दर और कम महंगाई के साथ आगे बढ़ रहा है, जो वैश्विक स्तर पर बहुत कम देखने को मिलता है। पीएम मोदी ने कहा, कि हमें फ्रेजाइल फाइव इकोनॉमी के रूप में छोड़ा गया था, लेकिन आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और बहुत जल्द तीसरे स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि एक समय ऐसी स्थिति बना दी गई थी कि दुनिया का कोई देश भारत से डील करने को तैयार नहीं होता था।

हंगामे के बीच विपक्षी सांसदों ने सदन से वाकआउट कर दिया। इस पर भी पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा, जो लोग थक गए, बिचारे चले गए, लेकिन कभी न कभी उन्हें जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान सत्ता पक्ष के सांसद मेज थपथपाते रहे, जबकि विपक्ष की नारेबाजी और वाकआउट ने सदन की कार्यवाही को और तनावपूर्ण बना दिया।

पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत उत्तराखंड को बड़ी सौगात, शहरी गरीबों के लिए आवास निर्माण को नई गतिः त्रिवेन्द्र सिंह रावत

पथ प्रवाह, नई दिल्ली।

पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा संसद में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के अंतर्गत उत्तराखंड में आवास निर्माण की प्रगति और भविष्य की योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है।

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू द्वारा दिए गए लिखित उत्तर में बताया गया कि केंद्र सरकार का लक्ष्य शहरी गरीबों को सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के आवास उपलब्ध कराना है। इसी उद्देश्य से 01 सितंबर 2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत अगले पाँच वर्षों में देशभर में 1 करोड़ अतिरिक्त शहरी आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि उत्तराखंड में अब तक पीएमएवाई-यू के अंतर्गत कुल 66,577 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से

2,972 आवास पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत हैं। इनमें से 63,525 आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा 51,565 आवास पूर्ण कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित और पारदर्शी योजना है, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाता है। नागरिक स्वयं भी योजना के एकीकृत पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, जिससे जरूरतमंदों तक सहायता सीधे पहुँच रही है। उन्होंने बताया कि पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत लाभार्थी आधारित निर्माण, किफायती आवास साझेदारी, किफायती किराया आवास और ब्याज सब्सिडी जैसी योजनाओं के माध्यम से उत्तराखंड सहित देशभर के शहरी गरीबों को आवासीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार शहरी गरीबों के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पीएमएवाई-यू 2.0 उत्तराखंड के शहरी परिवारों के लिए आशा की नई किरण है। उत्तराखंड को आवास के क्षेत्र में निरंतर प्राथमिकता दिए जाने को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।

लोकसभा में पीएम की स्पीच के बिना धन्यवाद प्रस्ताव पास

2004 के बाद ऐसा पहली बार

नई दिल्ली। बजट सत्र के 7वें दिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हंगामे के बीच पास हो गया। 2004 के बाद पहली बार यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री के भाषण के बिना पास हुआ है। इससे पहले 10 जून 2004 को विपक्ष ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को धन्यवाद प्रस्ताव पर नहीं बोलने दिया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। स्पीच के दौरान विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए, तानाशाही नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि खड़गे जी की उम्र देखते हुए उन्हें बैठकर नारे लगाने की इजाजत दी जाए। इसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। प्रधानमंत्री ने एक घंटा 27 मिनट भाषण दिया। उन्होंने बिना विपक्ष जोरदार हमला किया। मोदी ने कहा कि ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है, जो मोदी की कब्र खोदने की बात करते हैं। ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादा का अपमान नहीं है पीएम बोले- टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट, डीएमके दशकों से केंद्र में सत्ता का हिस्सा रहे। उनकी पहचान क्या बनी, उनके वक्त डील के नाम पर बोफोर्स याद आता है। आज की चर्चा गौरव से होती है। गुरुवार को लोकसभा शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। इस पर स्पीकर ने पहली बार 65 सेकंड के भीतर, दूसरी बार 5 मिनट में और तीसरी बार 2 मिनट में कार्यवाही स्थगित कर दी। लोकसभा 3 बजे दोबारा शुरू होगी। इस बीच कांग्रेस के लोकसभा से निलंबित सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि जब तक लोकसभा में राहुल गांधी को अपनी बात रखने की इजाजत नहीं दी जाती, तब तक विपक्ष पीएम नरेंद्र मोदी को सदन में बोलने नहीं देगा। राज्यसभा में भी राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने से रोकने के मुद्दे पर हंगामा हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल को पूर्व सेना प्रमुख की अप्रकाशित किताब पर नहीं बोलने दिया, मैं उसपर यहां बोलूंगा। इस पर उपसभापति ने उन्हें रोक दिया।

एक नजर

बाप को छुड़ाने के लिए बेटे ने यूपी पुलिस पर किया हमला ; तीन आरोपी गिरफ्तार

पथ प्रवाह, हरिद्वार। धोखाधड़ी के एक आरोपी को पुलिस हिरासत से छुड़ाने की कोशिश में दबंगई दिखाना एक युवक और उसके साथियों को भारी पड़ गया। कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस पर हुए जानलेवा हमले के मामले में ज्वालापुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना में प्रयुक्त थार और स्कॉर्पियो वाहनों को भी कब्जे में ले लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। घटना 03 फरवरी 2026 की है। थाना छपार, जनपद मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) के उप-निरीक्षक अनुराग सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ धोखाधड़ी के मामले में वांछित अभियुक्त संजय पुत्र राजपाल को ज्वालापुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर पुलिस वाहन से ले जा रहे थे। इसी दौरान भूमानंद अस्पताल के पास अभियुक्त के पुत्र ईशान्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने पिता को छुड़ाने का प्रयास किया। आरोप है कि ईशान्त और उसके साथियों ने अपनी स्कॉर्पियो और थार गाड़ियों से पुलिस वाहन को टक्कर मारकर जानलेवा हमला किया और सरकारी कार्य में गंभीर रूप से बाधा डाली।

इस हमले में पुलिस टीम के कई सदस्य घायल हो गए, वहीं सरकारी वाहन भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली ज्वालापुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मुस्तैदी दिखाते हुए तीन आरोपियों को मौके से ही दबोच लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त दोनों वाहनों को भी जब्त कर लिया है।

इस संबंध में उप-निरीक्षक अनुराग सिंह की लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली ज्वालापुर में मुकदमा अपराध संख्या 93/2026 दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 121(1), 132, 191(2), 324(4), 351(2), 352 व 61(2) के तहत मामला पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों में ईशान्त पुत्र संजय, शिवम मलिक पुत्र अनुज मलिक और अमन पुत्र गजेंद्र शामिल हैं, जो सभी सुभाष नगर, कोतवाली ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार के निवासी हैं। पुलिस टीम में वरिष्ठ उप-निरीक्षक खेमेन्द्र गंगवार, उप-निरीक्षक रविंद्र जोशी, कांस्टेबल मनोज डोभाल, भागचंद और ताजवर चौहान शामिल रहे।

महाराष्ट्र के दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अस्थियां गंगा में हुई प्रभावित

पथ प्रवाह, हरिद्वार। प्लेन क्रैश हादसे में मारे गए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अस्थियां गुरूवार को गंगा में विधि विधान के साथ प्रवाहित की गई। अजीत पवार की अस्थियां सवेरे राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष धीरज शर्मा हरिद्वार के वीआईपी घाट लेकर पहुंचे, जहां अजित पवार के पुरोहित अभिषेक झा ने विधि विधान के साथ अस्थियों का विसर्जन कराया।

अस्थि विसर्जन करने आए राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष धीरज शर्मा ने बताया कि राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस ने दिवंगत नेता अजीत दादा की याद में एक भव्य अस्थि कलश यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। इस यात्रा का विधिवत शुभारंभ धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा तट पर हिंदू रीति-रिवाजों के साथ किया गया। उन्होंने बताया कि यह यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर काशी, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी, गुजरात में साबरमती, और जम्मू-कश्मीर में चेनाब नदी तक जाएगी। यात्रा का विस्तार दक्षिण भारत के रामेश्वरम और कन्याकुमारी तक होगा, जहाँ विभिन्न पवित्र नदियों में उनकी अस्थियों को प्रवाहित किया जाएगा। उन्होंने बताया की अजीत दादा की विचारधारा को मानने वाले लोग पूरे हिंदुस्तान में हैं। हम इस यात्रा के माध्यम से हर उस कार्यकर्ता और प्रशंसक को उनके अंतिम दर्शन का अवसर देना चाहते हैं जो उनसे जुड़ाव महसूस करता है। इस कार्यक्रम में धीरज शर्मा के साथ तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित, पूर्व मेयर हरिद्वार मनोज गर्ग, डॉ बृजेश यादव, डॉ विमल शर्मा, सौरभ आहूजा, युवराज सिंह, अंकित चौधरी आदि सहित सैकड़ों एनसीपी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

ब्याज का झांसा देकर करोड़ों की ठगी का भंडाफोड़, दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार

पथ प्रवाह, नैनीताल

जनता की मेहनत की कमाई को अधिक ब्याज और गारंटी का झांसा देकर हड़पने वाले एक बड़े वित्तीय घोटाले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर की गई इस प्रभावी कार्रवाई में वर्ष 2017 से सक्रिय एक फर्जी सहकारिता संस्था के दो मुख्य संचालकों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने हजारों निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी की। उत्कृष्ट कार्य के लिए एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने पुलिस टीम को 2500 नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने लंबे समय से लंबित गंभीर आपराधिक मामलों में त्वरित कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी मनोज कुमार कात्याल, क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी अमित सैनी एवं क्षेत्राधिकारी रामनगर सुमित पांडेय के पर्यवेक्षण में

प्रभारी निरीक्षक रामनगर सुशील कुमार के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई।

जांच के दौरान कोतवाली रामनगर में दर्ज एफआईआर संख्या 246/23, धारा 409 IPC के तहत एक बड़े वित्तीय घोटाले का सफल अनावरण किया गया। अभियुक्तों द्वारा 'देवभूमि बहुदेशीय स्वायत्त सहकारिता' नामक संस्था हल्द्वानी (कपिल कॉम्प्लेक्स, मुखानी) और रामनगर में खोली गई थी। उत्तराखंड सरकार से पंजीकरण का हवाला देकर और अधिक ब्याज व गारंटी का लालच देकर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल सहित कई जनपदों के भोले-भाले नागरिकों से निवेश कराया गया।

पुलिस जांच में सामने आया कि संस्था के संचालक हेमचंद पंत (अध्यक्ष) और विकास दुर्गापाल (सचिव) ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर करीब 6 करोड़ 80 लाख रुपये का गबन किया और फरार हो गए। दोनों शाखाएं बंद पाई गईं तथा अभियुक्तों के बैंक खातों में करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन का खुलासा हुआ। न्यायालय से वारंट और कुर्की आदेश प्राप्त कर दिल्ली, हरियाणा और लखनऊ में लगातार दबिश दी गई।

04 फरवरी 2026 को दोनों मुख्य अभियुक्तों को लालकुआं क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य थानों में भी धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हैं। गिरोह में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता की भी संभावना जताई गई है, जिनकी तलाश जारी है।

गिरफ्तारी टीम में

उपनिरीक्षक दीपक सिंह बिष्ट (लालकुआं), कांस्टेबल आनंदपुरी, कांस्टेबल जितेंद्र बिष्ट शामिल रहे।

उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं/विभिन्न औद्यानिक गतिविधियों हेतु कृषकों/उद्यानपतियों को प्रदान की जाने वाली राज सहायता का विवरण

प्रत्रांक 2645/विज्ञापन/2025-26 **दिनांकः 05.02.2026**

क्र. सं.	घटक का नाम	मद	राजसहायता का विवरण	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी
	केन्द्रीय योजनायें			
1.	नये उद्यानों की स्थापना			
अ.	फल क्षेत्रफल विस्तार सामान्य	इन्टीग्रटिड (ड्रिप सहित)	50000.00 प्रति है0	4 हैक्टेयर
ब.	सब्जी क्षेत्रफल विस्तार	संकर प्रजाति की सब्जियां की खेती	50 प्रतिशत अर्थात 25000.00 प्र0है0	2 हैक्टेयर
स.	मशाला क्षेत्र विस्तार	बीज एवं कन्द वाली मशाला की खेती	50 प्रतिशत अर्थात् 15000.00 प्र0है0	4 हैक्टेयर
द.	पुष्प क्षेत्र विस्तार	डंडीयुक्त	रू0 50000.00 प्रति है0	2 हैक्टेयर
य.	मशरूम उत्पाद	मशरूम उत्पादन यूनिट	रू. 20.00 लाख प्रति इकाई लागत पर	अधिकतम 8.00 लाख रूपये
2.	जल प्रबन्धन व्यवस्था	नई ट्यूबवैल की स्थापना	50 प्रतिशत या रू. 20000.00 प्रति इकाई लागत	1 नग
1.	औद्यानिक यन्त्रीकरण	टैक्टर 20 (पी.टी.ओ. एच.पी.तक	रू. 3.00 लाख प्र0 इकाई का 35 प्रतिशत अनु.जा0 अनु.ज.जा., लघु/सीमान्त लाभार्थियों हेतु।	1 इकाई
3.	राज्य सैक्टर			
अ.	वर्मीकम्पोस्ट यूनिट का निर्माण	वर्मीकम्पोस्ट यूनिट की स्थापना	रू. 33.300 प्रति ईकाई की लागत का 50 प्रतिशत	1 इकाई रू. 24997.00
	पालीहाउस के पॉलीथिन बदलाव योजना	पुराने पालीहाउस की जीर्णशिर्ण पॉलीथिन	रू. 50 प्रतिवर्ग मीटर का 50 प्रतिशत	4000 वर्ग मीटर
	नि:शुल्क फलपौध वितरण			नि:शुल्क
अ.	9113– उन्नत किस्म की रोपण सामग्री का उत्पादन/पौद्योलय विकास	1. कीटव्याधि की रोकथाम	60 प्रतिशत	5000.00 प्र0है0
		2. प्लास्टिक क्रेटस वितरण	50 प्रतिशत	आवश्यकता अनुसार

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

सनातन संस्कृति और राष्ट्र चेतना के प्रतीक थे सत्यमित्रानंद गिरी महाराज: मुख्यमंत्री धामी

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को हरिद्वार स्थित सप्तऋषि आश्रम मैदान में आयोजित 'संत सम्मेलन' में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिन महापुरुषों ने अपना सम्पूर्ण जीवन राष्ट्रधर्म, सेवा, त्याग और करुणा के लिए समर्पित किया, वे केवल संन्यासी नहीं बल्कि राष्ट्र चेतना से जुड़े दिव्य संत थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्यमित्रानंद गिरी महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान को सामाजिक सेवा से जोड़ते हुए ऐसा जीवन दर्शन प्रस्तुत किया, जिससे अनगिनत लोगों को सेवा और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली। उन्होंने भारत माता मंदिर की स्थापना कर सनातन संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का कार्य किया, जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का केन्द्र बना हुआ है। वर्ष 1998 के कुंभ मेले में उन्हें आचार्य महामंडलेश्वर बनाया गया, जिसके बाद अब तक 10 लाख से अधिक नागा साधुओं को दीक्षा प्रदान की गई। कहा कि सत्यमित्रानंद गिरी महाराज की मूर्ति स्थापना नई पीढ़ी के लिए आध्यात्मिक जागरण का माध्यम बनेगी। संत परंपरा किसी एक पंथ या संप्रदाय तक सीमित न होकर वसुधैव कुटुंबकम के भाव से सम्पूर्ण विश्व को जोड़ने का कार्य करती है। सनातन धर्म मानव निर्मित नहीं, बल्कि शाश्वत सिद्धांतों पर आधारित है,

जो समय के साथ चलता है और कभी पराजित नहीं होता।

जिहादी मानसिकताओं के विरूद्ध कठोर कार्यवाही

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून, सख्त दंगारोधी कानून, तथा लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी जिहादी मानसिकताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर सभी नागरिकों के लिए समान कानून की स्थापना की गई है। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 28 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक उत्थान का नया युग प्रारंभ हुआ है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण तथा बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान जैसे कार्य भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

भारत माता मंदिर देश की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हरिद्वार में गंगा तट पर स्थित भारत माता मंदिर देश की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले की तैयारियाँ की जा रही हैं और महाराज जी का जीवन निरंतर सद्कर्म और साधना से प्रेरित रहा। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत में बीते वर्षों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है और आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने कहा कि जल, थल और वायु मार्गों का तीव्र विकास हुआ है तथा युवा शक्ति देश को विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर कर रही है। संत समाज भारतीय संस्कृति को सुदृढ़ करने और देश को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य कर रहा है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि संतों का सान्निध्य जीवन के दुखों का समाधान है। भारत की पहचान सनातन संस्कृति से है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ देश की आध्यात्मिक एकता के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि परमात्मा एक है, उसकी अभिव्यक्ति विभिन्न आस्थाओं के माध्यम से होती है।

संत सम्मेलन में मौजूद रहे ये अतिथि

कार्यक्रम में जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज ,शंकराचार्य राजराजेश्वराश्रम महाराज योग गुरु बाबा रामदेव, ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी, निर्मल अखाड़े के श्रीमहंत ज्ञानदेव शास्त्री जी, ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी,महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद महाराज,निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विशोखानंद भारती जी, श्रीमहंत देवानंद सरस्वती,संघ संचालक राम गोपाल कृष्ण,प्रज्ञा भारती,कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम,श्रीमहंत नारायण गिरी महाराज,जूना अखाड़े के महामंत्री महेश पूरी,महामंडलेश्वर हरिचेतना नंद जी, विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष आलोक कुमार, महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी,सुरेश चौहान,विधायक हरिद्वार मदन कौशिक,विधायक रुड़की प्रदीप बत्रा,राज्य मंत्री विनय रोहिला, जिलाध्यक्ष भाजपा आशुतोष शर्मा,आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे, मेलाधिकारी श्रीमती सोनिका,जिलाधिकारी मयूर दीक्षित,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल सहित बड़ी संख्या में साधु-संत,श्रद्धालु , जनप्रतिनिधि एवं अनुयाई उपस्थित रहे।

एक नजर

सीआईएसएफ परिसर से चुराए गए कॉपर वायर के साथ एक गिरफ्तार

पथ प्रवाह, हरिद्वार। सीआईएसएफ परिसर से चोरी किये गए कॉपर वायर के साथ एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के पास से चोरी किये गए 14 कॉपर वायर रोल बरामद हुए हैं। कोतवाली रानीपुर पुलिस के मुताबिक ष्ट.ढ्ढ.स्.स्न क्काश्वरु रानीपुर हरिद्वार के निरीक्षक दयाल सिंह, उ0नि0 सचिन कुमार, का0 पी0के0 अग्नीहोत्री द्वारा सूचना दी कि उनके द्वारा ष्ट.ढ्ढ.स्.स्न कैम्पस टॉवर- 4 के समीप एक संदिग्ध व्यक्ति को 14 रोल कॉपर वायर चोरी करते हुये पकडा गया है। ष्ट.ढ्ढ.स्.स्न. एवं बी.एच.ई.एल. कर्मियों द्वारा चोरी किये गये 14 रोल कॉपर वायर के थाना रानीपुर पर लाया गया। रानीपुर पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभिषेक को हिरासत में लेकर आरोपी के कब्जे से कुल 14 रोल कॉपर वायर कीमती करीब 02 लाख रूपये को कब्जे में लिया गया व मनीष कुमार सिंह वरि0 अभियंता मानव संसाधन (सामान्य प्रशासन) की तहरीर पर मु0अ0सं0 37/26 धारा 303(2),317(2) बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

खेडाजट्ट गोलीकांड में एक और गिरफ्तारी, अब तक तीन अभियुक्त गिरफ्तार

पथ प्रवाह, हरिद्वार। खेडाजट्ट में हुए गोलीकांड की घटना में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। कोतवाली मंगलौर पुलिस द्वारा इस प्रकरण में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार किये गए हैं। इनमें से दो को पूर्व में गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही के बाद जेल भेजा गया है। घटना में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक बीती 3 जनवरी की सायं को कोतवाली मंगलौर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खेडाजट्ट में दो पक्षों के अराजक तत्वों द्वारा आपसी झगड़ा कर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। उक्त घटना के संबंध में पूर्व में 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध असलहा बरामद किया जा चुका है। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा शेष आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु सख्त निर्देश जारी किए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मंगलौर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर गुरूवार को ग्राम खेडाजट्ट गोलीकांड से संबंधित दूसरे पक्ष के एक और आरोपी शिव चौधरी पुत्र उधम सिंह को चौकी नारसन क्षेत्र से हिरासत में लिया गया। आरोपी के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा बरामद किया गया। आरोपी के विरुद्ध नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कर कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जगद्गुरू आश्रम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और मोहन यादव

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने हरिद्वार के कनखल स्थित जगतगुरु आश्रम पहुंचकर जगद्गुरू शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज से शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री ने जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज को अंगवस्त्र भेंटकर शंकराचार्य जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की खुशहाली, प्रगति एवं आध्यात्मिक चर्चा की और महाराज के दिव्य सानिध्य में मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव, राज्य मंत्री विनय रोहिला, कुंभ मेलाधिकारी सोनिका,

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल आदि मौजूद रहे।

बहुउद्देशीय शिविर में 251 लोगों को सरकार की योजनाओं से किया गया लाभान्वित

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

मुख्य विकास अधिकारी डॉ ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में विकासखंड रुड़की के न्याय पंचायत खंजरपुर पंचायत घर टोडा कल्याणपुर अहतमाल में जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार शिविर में विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित जन कल्याणकारी योजनों से 2251 क्षेत्रवासियों को लाभान्वित किया गया। विभिन्न विभागों के माध्यम से 1245 लोगों को विभिन्न प्रमाण पत्र निर्गत किए गए, इस शिविर में 5238 लोगों द्वारा किया गया प्रतिभाग।

आयोजित शिविर ने क्षेत्रवासियों द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित 66 समस्याएं दर्ज कराई गई, जिसमें 46 समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया, शेष समस्याओं को त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपाध्यक्ष, समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति (राज्यमंत्री स्तर) देशराज कर्णवाल ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों में यह अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुँचाना है तथा उनकी समस्याओं का त्वरित गति से समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार आयोजित हो रहे शिविरो में भारी संख्या में ग्रामीण पहुंच रहे है तथा शिविर में विभिन्न विभागों की जन-कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इस दौरान क्षेत्रवासियों द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 66 समस्याएं दर्ज कराई गईं, जिनमें से 46 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।जिनमें भूमि विवाद, अतिक्रमण, विद्युत विभाग के बिल, जलभराव, चकरोड़ एवं साफ-सफाई से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रहीं। उन्होंने कहा कि बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से क्षेत्रीय जनता को भरपूर लाभ हो रहा है। राज्य मंत्री एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री/भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष द्वारा शिविर में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टालों का भी निरीक्षण किया। मुख्य विकास अधिकारी ने क्षेत्रवासियों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र ने संबंधित अधिकारियों को कहा कि जिन शिकायतों का जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में निस्तारित नहीं हो पाया है उन शिकायतों का तत्परता से निराकरण करना सुनाश्चित करे। शिविर में विधायक उमेश कुमार शर्मा, ग्राम प्रधान वाजिद अली, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, खंड विकास अधिकारी सुमन कोटियाल सहित क्षेत्र के समस्त ग्राम प्रधानगण, पंचायत सदस्यगण, अधिकारी व कर्मचारीगण और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।

संपादकीय

सिविल मामलों में पुलिस के अनावश्यक हस्तक्षेप पर सख्त निर्देश राज्य की कानून-व्यवस्था और न्याय प्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण

उत्तराखंड में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दीपम सेठ द्वारा सिविल मामलों में पुलिस के अनावश्यक हस्तक्षेप पर सख्त निर्देश राज्य की कानून-व्यवस्था और न्याय प्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भूमि, संपत्ति और पारिवारिक विवादों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इन निजी विवादों को पुलिस के माध्यम से सुलझाने की प्रवृत्ति न केवल पुलिस पर अतिरिक्त दबाव डालती है, बल्कि कानून के मूल सिद्धांतों को भी कमजोर करती है।

उत्तराखंड की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां इसे अन्य राज्यों से अलग बनाती हैं। यहां भूमि का बड़ा हिस्सा पुश्तैनी है, जिसमें पीढ़ियों से चले आ रहे बंटवारे और मालिकाना हक को लेकर विवाद आम हैं। कई बार जमीन से जुड़े मामलों में पक्षकार पुलिस पर दबाव बनाकर अपने पक्ष में कार्रवाई करवाने का प्रयास करते हैं। इससे न केवल निष्पक्षता प्रभावित होती है, बल्कि पुलिस को ऐसे मामलों में घसीट लिया जाता है, जिनका निपटारा केवल दीवानी न्यायालयों में ही संभव है।

डीजीपी का यह स्पष्ट निर्देश कि पुलिस का कार्य अपराध रोकना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, न कि निजी सिविल विवादों में मध्यस्थ बनना, समय की मांग है। राज्य में पहले से ही पुलिस बल पर आपराधिक मामलों, आपदा प्रबंधन, चारधाम यात्रा, कुंभ जैसे बड़े आयोजनों और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा का भारी दायित्व रहता है। ऐसे में सिविल मामलों में उलझना पुलिस की ऊर्जा और संसाधनों का दुरुपयोग है।

उत्तराखंड में पारिवारिक विवाद, किरायेदार-मकान मालिक के झगड़े, पैसों की वसूली और अनुबंध उल्लंघन जैसे मामलों को अक्सर आपराधिक रंग देकर थानों तक पहुंचाया जाता है। इससे आम जनता में यह भ्रम पैदा होता है कि हर विवाद का समाधान पुलिस ही करेगी। डीजीपी का यह निर्देश इस गलत धारणा को तोड़ने की दिशा में अहम कदम है। साथ ही यह भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर भी अंकुश लगाने में सहायक होगा, क्योंकि सिविल मामलों में पुलिस हस्तक्षेप को लेकर अक्सर पक्षपात और दबाव के आरोप लगते रहे हैं।

सिविल मामलों का उद्देश्य किसी को जेल भेजना नहीं, बल्कि कानून के दायरे में अधिकारों की रक्षा और नुकसान की भरपाई करना होता है। भूमि विवादों में मालिकाना हक तय करना, पारिवारिक मामलों में भरण-पोषण या कस्टडी का निर्णय देना पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यह कार्य न्यायालयों का है, जहां साक्ष्य और कानून के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लिया जाता है।

साधारण शब्दों में, यदि किसी विवाद में मारपीट, धोखाधड़ी, चोरी या कोई गंभीर आपराधिक कृत्य नहीं हुआ है, तो पुलिस को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उत्तराखंड जैसे संवेदनशील और संसाधन-सीमित राज्य में डीजीपी दीपम सेठ का यह निर्देश पुलिस को उसके मूल कर्तव्यों पर केंद्रित करेगा और जनता को सही कानूनी रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। इससे न केवल पुलिस-जन विश्वास मजबूत होगा, बल्कि न्याय व्यवस्था भी अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनेगी।

बैंकों में 3.4 लाख करोड़ का सोना गिरवी, बैंकों का जोखिम बढ़ा

सनत कुमार जैन

सोने की कीमतों में गिरावट से बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों की चिंता बढ़ गई है। देश में गोल्ड लोन का चलन बढ़ता जा रहा है। लोग अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए सोना गिरवी रखकर लोन ले रहे हैं। हाल ही में सोने की कीमतों में तेज वृद्धि और उसके बाद तेजी के साथ दामों में गिरावट ने बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों की ऋण व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 9 करोड़ लोगों ने सोना गिरवी रख कर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कर्ज लिया है। जिसके चलते लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपये मूल्य का सोना बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के पास गिरवी रखा हुआ है। सोने के दाम में हालिया गिरावट ने इस पूरे तंत्र को हिला दिया है। बैंक और वित्तीय संस्थान सोने की कीमत का 75 फ़ीसदी से 90 फ़ीसदी तक फाइनेंस कर देते हैं। ऋण देने के जो नियम बना रखे हैं उसके अनुसार यदि दाम घटते हैं तो ऐसी स्थिति में ऋणधारक को ब्याज की मार्जिन मनी चुकानी पड़ती है। यदि वह मार्जिन नहीं दे पता है तो ऐसी स्थिति में बैंक और वित्तीय संस्थानों को अधिकार है कि वह सोने की नीलामी करके अपना पैसा वसूल कर लें। बीते वर्षों में सोने की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण गोल्ड लोन को सुरक्षित कर्ज मानते हुए बैंकों ने बड़े पैमाने पर सोने पर कर्ज को बढ़ावा दिया है। लोगों ने भी बढ़ी हुई कीमतों का फायदा उठाकर ज्यादा कर्ज लिया। कई मामलों में टॉप-अप लोन भी प्राप्त किया है। अब सोने के दाम अप्रत्याशित रूप से घटने के कारण गिरवी रखे गए सोने का मूल्य कम हो गया है। कर्ज की राशि से सोने की कीमत कम हो गई है। ऐसी स्थिति में बैंकों द्वारा कर्जदारों से मार्जिन मनी जमा करने या अतिरिक्त सोना गिरवी रखने का दबाव बढ़ाया जा रहा है। समस्या यह है, गोल्ड लोन लेने वाले अधिकतर लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उनके पास ब्याज और मार्जिन मनी के रूप में जमा करने के लिए अतिरिक्त नकदी नहीं है। जिससे वह वित्तीय संस्थान द्वारा मांगी गई मार्जिन मनी को जमा कर सकें। अर्थ विशेषज्ञों का कहना है, अगर कर्ज न चुकाने की स्थिति में बड़े पैमाने पर वित्तीय संस्थाओं द्वारा सोने की नीलामी की जाएगी। ऐसी स्थिति में तो बाजार में सोने की आपूर्ति बढ़ेगी। जिससे सोने की कीमतों में और भी बड़ी गिरावट आ सकती है। इससे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का घाटा बढ़ सकता है। इसका असर बैलेंस शीट पर भी पड़ेगा। सोने और चांदी की कीमतों में जिस तरह की तेजी और मंदी देखने को मिल रही है, उसने वित्तीय संस्थानों की चिंता को बढ़ा दिया है। शेयर बाजार में भी लगातार गिरावट का दौर चला। जिसके कारण वित्तीय संस्थानों को शेयर बाजार में भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। बाजार में उपभोक्ता के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। जिसके कारण बाजार में मांग घट रही है। नौकरी और रोजगार पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव दिखने लगा है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और अन्य बैंक इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अर्थ विशेषज्ञों के अनुसार, अगर सोने की कीमतों में तेज गिरावट जारी रहती है तो यह संकट बैंकिंग व्यवस्था के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती बन सकता है। पिछले कुछ वर्षों से सोना गिरवी रखने में 75 से 90 फ़ीसदी तक लोन गिरवी रखने वालों को दिया जाता था। बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा सोने पर लोन लिया गया है। सोने में लिए गए ऋण का असर 9 करोड़ परिवारों पर सीधे रूप से देखने को मिल रहा है। जिस मध्यम वर्ग के पास सोना है, वह अपनी ज़रूरतें सोना गिरवी रखकर पूरी कर रहा था।

सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर

हर्षवर्धन पान्डे

लता की मखमली और जादुई आवाज की दुनिया दीवानी थी। उनकी आवाज़ दिल को छूती नहीं, बल्कि दिल में बस जाती थी। हर दिल अजीज लता मंगेशकर ने अपनी आवाज से हिंदी सिनेमा की गायकी में ऐसे चार चाँद लगाए कि हर कोई उनका मुरीद हुए बिना नहीं रह पाया। सही मायनों में हिंदी सिनेमा की गायकी की दुनिया को लता ने अपने मधुर स्वर से नई दिशा देने का काम किया। लता दीदी की वो आवाज हर किसी के दिल के तारों को आज भी झंकृत कर देती है। हिंदी सिनेमा के 100 बरस से अधिक के सफ़र में लता दीदी की गायकी सिल्वर स्क्रीन पर चार चाँद लगा देती है। एक ऐसी आवाज हिन्दी फ़िल्म संगीत में हमेशा के लिए अमर रहेगी।

लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। लता पांच भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। लता मंगेशकर का जन्म के वक्त नाम हेमा रखा गया था लेकिन कुछ साल बाद अपने थिएटर के एक पात्र लतिका के नाम पर, दीनानाथ जी ने उनका नाम लता रखा। लता मंगेशकर के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक क्लासिकल सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट थे। लता की तीन बहनें मीना, आशा, उषा और एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर थे। पांच साल की उम्र में ही लता जी ने अपने पिता से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी और थिएटर में एक्टिंग किया करती थी। जब वो स्कूल गयी तो वहां के बच्चों को संगीत सिखाने लगी लेकिन जब लता जी को अपनी बहन आशा को स्कूल लाने से मना किया गया तो उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया।सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर का भी बॉलीवुड में सफर इतना आसान नहीं था। काफी समय तक उन्हें कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला। प्रोजेक्ट नहीं मिलने की दो वजहें थीं। एक तो साल 1940 के दौर में जब उन्होंने फिल्मी दुनिया में एंट्री ली बॉलीवुड में नूर जहां और शमशाद का दबादबा था और दूसरा लता की आवाज़ की पिच काफी हाई थी और आवाज़ पतली, ऐसे में उस दौर के चलन में चल रहे गानों के मुताबिक आवाज भी फिट नहीं बैठती थी। प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी ने लता मंगेशकर की आवाज को पतली आवाज कहकर अपनी फिल्म शहीद में गाने से मना कर दिया था फिर म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर ने लता मंगेशकर को फिल्म मजबूर में दिल मेरा तोडा, कहीं का ना छोड़ा गीत गाने को कहा जो काफी सराहा गया । लता मंगेशकर के पिता नहीं चाहते थे कि वो फ़िल्मों के लिये गाने गाये लेकिन लता मंगेशकर बचपन से ही गायक बनना चाहती थीं। लता ने वसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फ़िल्म कीर्ती हसाल के लिये पहली बार गाना गाया था लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फ़िल्मों के लिये गाएं इसलिए इस गाने को फ़िल्म से निकाल दिया गया लेकिन वसंत जोगलेकर लता की प्रतिभा से काफी प्रभावित हुए । साल 1942 में उनके पिता इस दुनिया को छोड़ गए और लता मंगेशकर के कंधों पर परिवार को संभालने की सारी ज़िम्मेदारी आ गई ।

पिता की मौत के बाद लता को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफी संघर्ष करना पड़ा। इसी वजह से लता मंगेशकर ने 1942 से लेकर 1948 तक करीब 8 हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया। 40 के दशक में लता मंगेशकर जब फिल्मों में गाना शुरू किया तो वो लोकल पकड़कर अपने घर मलाड जाती थी। वहां से उतरकर पैदल स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज जाती। रास्ते में किशोर दा भी मिलते लेकिन वो एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। किशोर कुमार लता मंगेशकर की ओर देखते रहते। कभी हंसते। कभी अपने हाथ में पकड़ी छड़ी घुमाते रहते। लता मंगेशकर को किशोर कुमार की ये हरकत अजीब लगती थी ।हिंदी सिनेमा में उन्होंने पहला गाना साल 1943 में गाया। ये गाना था फिल्म गजाभाऊ का और इसके बोले थे माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू ।हालांकि इस गाने से लता को कुछ खास पहचान नहीं मिल सकी। लता मंगेशकर खेमचंद प्रकाश की एक फिल्म में गाना गा रही थी। एक दिन किशोर दा भी उनके पीछे-पीछे स्टूडियो पहुंच गए। लता मंगेशकर ने किशोर कुमार की खेमचंद से शिकायत की। तब खेमचंद ने लता को बताया कि किशोर कुमार अशोक कुमार के छोटे भाई हैं।

1948 में म्यूज़िक कंपोज़र गुलाम हैदर ने लता के बड़ा ब्रेक दिया जिसके बाद उनका संघर्ष का दौर खत्म हुआ और फिल्मी दुनिया में ऐसा सिक्का चला कि लोग उनकी आवाज के दीवाने हो गए। आज भी लता की गायकी सिल्वर स्क्रीन में चार चाँद लगा देती है। फिल्म मजबूर में लता मंगेशकर ने दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का न छोड़ा गाना गया। 1949 में उन्होंने फिल्म महल में गाया उनका गाना आएगा आनेवाला बेहद पसंद किया गया। इसके बाद उन्होंने दुलारी, बरसात और अंदाज़ में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। चंद महीनों में ही लता के प्रति लोगों का नजरिया बदला और उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली और फिर इसके बाद उन्हें मुड़कर पीछे नहीं देखना पड़ा। लता मंगेशकर ने फिल्म इंडस्ट्री के सभी दिग्गज म्यूज़िक डायरेक्टर्स और सिंगर्स के साथ काम किया ।1942 से अब तक वो 1000 से भी ज्यादा हिंदी फिल्मों और 36 से भी ज्यादा भाषाओं में गाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। लता मंगेशकर ने 1950 के दौर में कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी रूहानी आवाज़ का जादू बिखेरकर सुनने वालों को सुकून पहुंचाया। लता मंगेशकर ने 1950 के दौर में कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी रूहानी आवाज़ का जादू बिखेरकर सुनने वालों को सुकून पहुंचाया। उस दौरान उन्होंने बैजू बावरा, मदर इंडिया, देवदास और मधुमति जैसी हिट फिल्मों में गाने गाए. फिल्म मधुमति के गाने आजा रे परदेसी के लिए 1958 में लता मंगेशकर को पहला फिल्मफेयर मिला।

60, 70 और 80 के दशक में गाए गए लता मंगेशकर के ज्यादातर गाने ऑल टाइम हिट्स की कैटगरी में आते हैं। कहा जाता है कि बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स और एक्टर्स उनके साथ काम करने के लिए होड़ लगाया करते थे। साल 1977 में आई फिल्म किनारा में लता मंगेशकर नाम गुम जायेगा, चेहरा ये बदल जायेगा, मेरी आवाज़ ही, पहचान है, गर याद रहे गीत गाया। लता मंगेशकर की ये लाइनें उनके हर चाहने वाले को हमेशा याद रहेंगी। लता मंगेशकर ने 1950 के दौर में कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी रूहानी आवाज़ का जादू बिखेरकर सुनने वालों को सुकून पहुंचाया। उस दौरान उन्होंने बैजू बावरा, मदर इंडिया, देवदास और मधुमति जैसी हिट फिल्मों में गाने गाए ।फिल्म मधुमति के गाने आजा रे परदेसी के लिए 1958 में लता मंगेशकर को पहला फिल्मफेयर मिला। 60, 70 और 80 के दशक में गाए गए लता मंगेशकर के ज्यादातर गाने ऑल टाइम हिट्स की कैटगरी में आते हैं। कहा जाता है कि बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स और एक्टर्स उनके साथ काम करने के लिए होड़ लगाया करते थे। साल 1977 में आई फिल्म किनारा में लता मंगेशकर नाम गुम जायेगा, चेहरा ये बदल जायेगा, मेरी आवाज़ ही, पहचान है, गर याद रहे गीत गाया। लता मंगेशकर की ये लाइनें उनके हर चाहने वाले को हमेशा याद रहेंगी। उस दौरान उन्होंने बैजू बावरा, मदर इंडिया, देवदास और मधुमति जैसी हिट फिल्मों में गाने गाए। फिल्म मधुमति के गाने आजा रे परदेसी के लिए 1958 में लता मंगेशकर को पहला फिल्मफेयर मिला। लता मंगेशकर को साल 2001 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: मोदी नेतृत्व की वैश्विक दृढ़ता

ललित गर्ग

अंतरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक व्यापार के परिदृश्य में कोई भी समझौता केवल आंकड़ों या कर-प्रतिशतों तक सीमित नहीं होता, वह राष्ट्र की संप्रभुता, नेतृत्व की दृढ़ता और भविष्य की दिशा का भी संकेतक होता है। भारत और अमेरिका के बीच हालिया व्यापारिक सहमति, जिसके अंतर्गत प्रस्तावित 50 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है, इसी दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी घटना है। यह निर्णय केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक शक्ति-संतुलन और भारत की बढ़ती सौदेबाजी क्षमता का प्रमाण है। यहां 'देर आए, दुरुस्त आए' की कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है। जब अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर ऊँचे टैरिफ का दबाव बनाया गया था, तब यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था को अंततः झुकना पड़ेगा। वैश्विक व्यापार का हालिया इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि बड़ी शक्तियां अक्सर दबाव की राजनीति के माध्यम से अपने हित साधती हैं। किंतु फरवरी 2025 में आरंभ हुई इस व्यापारिक प्रक्रिया का फरवरी 2026 में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना यह दर्शाता है कि भारत ने न तो जल्दबाजी दिखाई और न ही अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता किया। भारत ने समय लिया, परिस्थितियों का मूल्यांकन किया और अंततः संतुलित व सम्मानजनक परिणाम प्राप्त किया। 50 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक की टैरिफ कटौती का तात्कालिक प्रभाव व्यापारिक जगत और शेयर बाजार में दिखाई दिया। निवेशकों का भरोसा लौटा, निर्यातकों को राहत मिली और बाजार में सकारात्मक संकेत उभरे। किंतु इस निर्णय का वास्तविक महत्व इससे कहीं अधिक व्यापक है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि भारत अब केवल नियमों का पालन करने वाला देश नहीं, बल्कि नियमों के निर्माण और पुनर्परिभाषा में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने वाला राष्ट्र बन चुका है। अमेरिका जैसी महाशक्ति का अपने रुख में नरमी लाना भारत की आर्थिक ताकत, रणनीतिक धैर्य और राजनीतिक आत्मविश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि उसमें संवाद है, पर दबाव के आगे समर्पण नहीं। चाहे वह रक्षा सहयोग हो, ऊर्जा सुरक्षा हो या व्यापारिक समझौते-हर क्षेत्र में भारत ने अपने हितों को केंद्र में रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया है।

इस व्यापारिक डील में भी भारत ने बिना झुके, बिना रुके और बिना कमजोर पड़े अपनी शर्तें स्पष्ट रूप से रखीं। यही कारण है कि अंततः अमेरिका को अपने प्रस्तावों में संशोधन करना पड़ा। यह केवल एक व्यापारिक जीत नहीं, बल्कि राजनीतिक परिपक्वता और नेतृत्व की दृढ़ता का उदाहरण है। इस समझौते से भारतीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एक उन्नत स्थिति प्राप्त होगी। कम टैरिफ का अर्थ है कि भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे, उनकी पहुंच बढ़ेगी और 'मेक इन इंडिया' को नया प्रोत्साहन मिलेगा। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, कृषि-आधारित उत्पाद और उभरते तकनीकी क्षेत्र-सभी को इससे दीर्घकालिक लाभ होने की संभावना है। भारत अब केवल सस्ता श्रम या कच्चा माल उपलब्ध कराने वाला देश नहीं, बल्कि मूल्यवर्धित उत्पादन और नवाचार की दिशा में अग्रसर अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में जिस संयम और आत्मविश्वास के साथ भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को 'निरंतर धैर्य का परिणाम' बताया, वह उनकी कूटनीतिक शैली का सार है। यह समझौता किसी अचानक हुए घटनाक्रम का नतीजा नहीं, बल्कि एक वर्ष तक चली रणनीतिक प्रतीक्षा, विकल्पों के विस्तार और संतुलित संवाद का परिणाम है। मोदी ने स्पष्ट संकेत दिया कि सरकार ने विपक्ष की आलोचनाओं और तात्कालिक दबावों के बावजूद धैर्य नहीं छोड़ा, क्योंकि वैश्विक व्यापार और भू-राजनीति में जल्दबाज़ी अक्सर महंगी पड़ती है। अमेरिका का झुकना किसी भावनात्मक मित्रता का परिणाम नहीं, बल्कि ठोस रणनीतिक विवशता का नतीजा है। बीते एक वर्ष में भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसके पास विकल्प हैं-रूस के साथ ऊर्जा सहयोग, यूरोपीय संघ के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में अपनी बढ़ती भूमिका।

खेल में कैरियर बनाएं पहाड़ के युवा : रेखा आर्या

पथ प्रवाह, सोमेश्वर/अल्मोड़ा

खेल मंत्री रेखा आर्या ने गुरुवार को सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के गांव गोविंदपुर में आयोजित मकर संक्रांति क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता और उपविजेता टीमों को सम्मानित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश में खेल ढांचे का लगातार विस्तार किया जा रहा है और अब दूर दराज की गांव में भी खेल मैदान और मिनी स्टेडियम बनाने पर सरकार का फोकस है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल संस्कृति विकसित हो रही है और ऐसे में पहाड़ी क्षेत्र के युवाओं को खेल को करियर के रूप में अपनाना चाहिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों के लिए पदक जीतने पर आउट ऑफ टर्न जॉब और सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर दी है। जिससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अब अपने करियर को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री ने टूर्नामेंट की विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही पिछले दिनों राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले युवाओं को भी मेडल

पहनकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष महेश नयाल, मंडल अध्यक्ष गणेश जलाल, जिला पंचायत सदस्य पुष्पा आर्य, विधायक प्रतिनिधि भुवन जोशी, गोपाल खोलिया, अशोक जलाल, राहुल खोलिया, गणेश अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

17 गांव के खिलाड़ियों को बांटी क्रिकेट किट

सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के कंडारकुआं मंडल में दीपाधार मंदिर प्रांगण में आसपास के 17 गांवों के युवक मंगल दल एवं क्रिकेट खेलने वाले युवाओं को क्रिकेट किट वितरित की गई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि युवा जब खेलकूद की गतिविधियों से जुड़ते हैं तो इससे न केवल नई खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, बल्कि युवाओं का शारीरिक व मानसिक विकास भी बेहतर होता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गांव-गांव तक विकास की योजनाएं पहुंचा रही है और सोमेश्वर क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में विकास कार्य कराए गए हैं। इस अवसर पर भुवन जोशी, हरीश परिहार, गोपाल सती, भुवन फर्त्याल, दीवान नेगी, जानकी, गोपाल राम, त्रिलोक सिंह रावत, भूपाल परिहार, धन सिंह रावत, तारा सिंह परिहार, विशन सिंह कन्वाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

एक नजर

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दिव्यांग बुजुर्ग को दी व्हीलचेयर

पथ प्रवाह, देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान आमजन की समस्याओं को सुना। इस दौरान एक गरीब एवं असहाय परिवार के सदस्य मंत्री जोशी से मिलने पहुँचे और उन्होंने अपने बुजुर्ग दिव्यांग परिजन की कठिन परिस्थितियों से अवगत कराया। परिवारजनों ने दिव्यांग बुजुर्ग के लिए व्हीलचेयर उपलब्ध कराने का मंत्री गणेश जोशी से आग्रह किया। परिवार की पीड़ा को समझते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संवेदनशीलता और तत्परता का परिचय देते हुए मौके पर ही नीला 60 वर्ष बुजुर्ग दिव्यांगजन ब्रह्माखाला निवासी को व्हीलचेयर प्रदान की। इसके साथ ही उन्होंने परिवार की आवश्यकता को देखते हुए रसद सामग्री एवं कंबल भी उपलब्ध कराए। मंत्री गणेश जोशी की इस मानवीय पहल से परिवारजनों के चेहरे पर खुशी और राहत दिखाई दी। सहायता मिलने पर परिवार के सभी सदस्यों ने मुस्कान के साथ 'थैंक्यू मंत्री जी' कहते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रति आभार व्यक्त किया।

एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने पुलिस उपाधीक्षकों के कार्यक्षेत्र में किया बदलाव

पथ प्रवाह, हरिद्वार। जनपद हरिद्वार में नव नियुक्त पुलिस उपाधीक्षक के जनपद आगमन के उपरांत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोबाल के निर्देश पर राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में आवश्यक प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। इस पुनर्वितरण का उद्देश्य पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक प्रभावी, संतुलित और जनहितकारी बनाना है, ताकि कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा सके। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि जितेंद्र चौधरी को पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो जनपद में संचालित पुलिस अभियानों एवं विशेष कार्यवाहियों की निगरानी करेंगे। निशा यादव को पुलिस अधीक्षक (तकनीकी एवं महिला सुरक्षा) नियुक्त किया गया है, जिनके दायित्वों में तकनीकी संसाधनों का बेहतर उपयोग, साइबर अपराधों पर नियंत्रण तथा महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई शामिल रहेगी। सुरेंद्र प्रसाद बलूनी को क्षेत्राधिकारी सदर, लाइन एवं कार्यालय का कार्यभार सौंपा गया है। वहीं संजय चौहान को क्षेत्राधिकारी सर्किल ज्वालापुर के साथ-साथ आंकिक कार्यालय की जिम्मेदारी दी गई है। नताशा सिंह को क्षेत्राधिकारी सर्किल रुड़की, अभिनय चौधरी को क्षेत्राधिकारी सर्किल मंगलौर तथा देवेंद्र सिंह नेगी को क्षेत्राधिकारी सर्किल लक्सर नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में विपेंद्र सिंह को क्षेत्राधिकारी यातायात, कुंभ मेला 2027 की तैयारियों एवं थाना बुग्गावाला की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।

देहरादून हत्याकांड की गहन जांच, एसपी मुख्यालय ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

पथ प्रवाह, देहरादून।

कोतवाली नगर क्षेत्र में घटित युवती की जघन्य हत्या के मामले को लेकर उत्तराखण्ड पुलिस पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ जांच में जुटी हुई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के क्रम में नामित जांच अधिकारी पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्रीमती विशाखा अशोक भदाणे (आईपीएस) ने प्रकरण की विस्तृत समीक्षा करते हुए घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया।

एसपी मुख्यालय श्रीमती विशाखा अशोक भदाणे (आईपीएस) ने घटनास्थल पर पहुंचकर हत्या से जुड़े प्रत्येक पहलू का गहन परीक्षण किया तथा मौके की परिस्थितियों, साक्ष्यों और पुलिस कार्यवाही का बारीकी से अवलोकन किया। इसके उपरांत उन्होंने पीड़ित परिवार से भेंट कर उनका पक्ष गंभीरतापूर्वक सुना और आवश्यक बयान दर्ज किए। इस दौरान परिवार से घटना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी जुटाई गईं। श्रीमती विशाखा अशोक भदाणे ने शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि इस संवेदनशील प्रकरण की जांच पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यपरक ढंग से की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जांच

के दौरान यदि किसी भी स्तर पर कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही या त्रुटि पाई जाती है, तो संबंधित के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा उत्तराखण्ड पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसपी मुख्यालय ने कोतवाली नगर एवं पुलिस चौकी खुड़बुड़ा पहुंचकर प्रकरण से संबंधित अभिलेखों, प्राप्त सूचनाओं, पुलिस रिस्पॉन्स और घटनाक्रम से जुड़े दस्तावेजों की भी गहन समीक्षा की। उन्होंने जांच के दौरान घटना के समय प्राप्त सूचनाओं पर की गई कार्यवाही, पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया एवं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के गहराई से परीक्षण के निर्देश दिए। पुलिस महानिरीक्षक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) उत्तराखण्ड सुनील कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा इस प्रकरण को अत्यंत संवेदनशील मानते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया गया है तथा जांच की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। दोषियों को शीघ्र न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।

चेन स्नेचर गिरफ्तार, स्ट्रीट क्राइम पर दून पुलिस का करारा प्रहार

पथ प्रवाह, देहरादून।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की सख्त कार्यशैली के चलते स्ट्रीट क्राइम के विरुद्ध दून पुलिस को एक और बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने वृद्ध महिला से चेन स्नेचिंग की घटना का त्वरित खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से छीनी गई चैन तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली है।

02 फरवरी 2026 को वादिनी मालमती राणा पत्नी स्व. चंद्र सिंह राणा, निवासी लेन नंबर-1 अनिकेत विहार, दून यूनिवर्सिटी रोड, देहरादून द्वारा थाना नेहरू कॉलोनी में तहरीर दी गई कि दून यूनिवर्सिटी रोड स्थित शिवम डेरी के पास अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने उनके गले से चैन छीन ली और मौके से फरार हो गया। तहरीर के आधार पर थाना नेहरू कॉलोनी में मु0अ0सं0 42/26 धारा 304(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना की गंभीरता देखते हुए एसएसपी देहरादून अजय सिंह के निर्देश पर तत्काल पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया तथा पूर्व में स्नेचिंग

की घटनाओं में शामिल अपराधियों का भौतिक सत्यापन किया गया। पुलिस टीम की त्वरित व अथक कार्रवाई के परिणामस्वरूप 04 फरवरी 2026 को मोथरोवाला पुल के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त शादाब अली पुत्र राशिद अली, निवासी नियामवाला, थाना डोईवाला, देहरादून (उम्र 25 वर्ष) के कब्जे से घटना में छीनी गई चैन तथा मोटरसाइकिल संख्या च07-1389 बरामद की गई। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह नशे का आदी है और नशे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम दिया। अभियुक्त पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल जा चुका है। घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है।

पुलिस टीमः

उ0नि0 प्रवीन पुंडीर (चौकी प्रभारी बाईपास), हे0का0 विद्यासागर, का0 श्रीकांत ध्यानी, का0 बृजमोहन रावत, का0 विनोद बचकोटी, का0 संदीप छाबड़ी, का0 अर्जुन कुमार

जिलाधिकारी ने किया बड़कोट तहसील, बड़कोट कोतवाली और नौगांव ब्लॉक मुख्यालय का निरीक्षण

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने गुरुवार सायं को थाना बड़कोट के निरीक्षण के दौरान मालखाना और बंदीगृह की स्थिति जांची। मालखाना से डिस्पोज प्रक्रिया की जानकारी की साथ ही उपस्तिथि रजिस्टर का परीक्षण किया और सीसीटीवी के नेटवर्क का भी जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसके लिए पुलिस एवं प्रशासन समन्वय के साथ कार्य करना जरूरी है। इस दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न मामलों में दर्ज वादों की भी जानकारी ली।

तहसील कार्यलय बड़कोट के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी विभिन्न कक्षों, अभिलेखागार, मीटिंग हॉल का अवलोकन किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ई-ऑफ़िस का प्रयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा अभिलेखों का रख-रखाव सुव्यवस्थित ढंग से रखने के निर्देश दिए। तथा किसी भी संसाधन और अन्य उपकरणों की आवश्यकता होने पर जिला प्रशासन को अवगत कराने को कहा।

नौगांव ब्लॉक मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी ने कार्यबल और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रधान संघ के अध्यक्ष त्रिपन रावत द्वारा एसएनए स्पर्श पोर्टल को लेकर आ रही समस्या से अवगत कराया गया जिस पर जिलाधिकारी द्वारा तत्काल राज्य समन्वयक मनरेगा सुधा तोमर से फोन पर वार्ता कर पोर्टल की वर्तमान स्थिति और आ रही समस्या के जल्द निराकरण करने के लिये कहा। इस दौरान खंड विकास अधिकारी द्वारा सहायक लेखाकार के रिक्त पद के कारण कार्य में आ रही समस्या से अवगत कराया इस संबंध में जिलाधिकारी ने सीडीओ के माध्यम से प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पीएम आवास,अंत्योदय और लखपति दीदी योजना में स्थिति सुधारने को और बेहतर करने के निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने 15 फरवरी से शुरू हो रहे एसआईआर मैपिंग में ब्लॉक तथा तहसील को सहयोग और समन्वय स्थापित करके कार्य करने के निर्देश दिये।

इस दौरान उपजिलाधिकारी मुकेश चन्द रमोला, खंड विकास अधिकारी प्रकाश पंवार, तहसीलदार रेनू सैनी,प्रभारी निरीक्षक सुभाष चंद सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

एक नजर

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट संबंधी प्राथमिकी पर हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों को बरकरार रखा

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामले में प्राथमिकी दर्ज करने को विनियमित करने संबंधी तेलंगाना उच्च न्यायालय के बनाये दिशा-निर्देशों को सही ठहराया है। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की एक पीठ ने गुरूवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए तेलंगाना राज्य की दायर विशेष अनुमति याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया है। इन याचिकाओं में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गयी थी। इस फैसले में तीन प्राथमिकी रद्द कर दी गयी थी और सोशल मीडिया सामग्री पर आधारित आपराधिक कार्यवाहियों से निपटते समय पुलिस और न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिए विस्तृत परिचालन दिशा-निर्देश निर्धारित किये थे। इस चुनौती याचिका में दखल देने से मना करते हुए न्यायालय ने कहा कि उसने गाइडलाइंस की 'बारीकी' से जांच की है और उन्हें बदलने का कोई कारण नहीं मिला। पीठ ने कहा, 'हमने पैरा 29 की पूरी जांच की है। हमारा मानना है कि हमें उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश में दखल नहीं देना चाहिए। इसमें उच्च न्यायालय का जारी दिशा-निर्देश भी शामिल हैं।

अपने आदेश में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने नल्ला बालू के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की आलोचना करने वाली उनकी एक्स पर की गयी पोस्ट के खिलाफ दर्ज तीन प्राथमिकी रद्द कर दी। उच्च न्यायालय ने यह माना था कि पोस्ट हालांकि आलोचनात्मक थे, लेकिन वे वैध राजनीतिक अभिव्यक्ति के दायरे में आते थे। इसके अलावा शिकायतों में विशिष्ट विवरणों की कमी थी और शिकायतकर्ताओं के पास इस मामले में हस्तक्षेप या शिकायत दर्ज करने के कानूनी अधिकार का अभाव था। न्यायालय ने पाया कि आपराधिक कार्यवाही का जारी रहना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि शत्रुता को बढ़ावा देने, सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा या राजद्रोह जैसे अपराधों के लिए प्राथमिकी केवल तभी दर्ज की जा सकती है, जब प्रथम दृष्टया ऐसा मामला बनता हो जिससे हिंसा, नफरत या सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाने के लिए उकसावे का पता चलता हो।

उच्च न्यायालय के जारी किये गये परिचालन दिशा-निर्देशों में मानहानि या इसी तरह के अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज करने से पहले सुनवाई के अधिकार का सत्यापन, संज्ञेय मामलों में वैधानिक तत्वों की पुष्टि करने के लिए प्रारंभिक जांच का संचालन और राजनीतिक भाषण से जुड़े मामलों में एक उच्च सीमा का अनुप्रयोग शामिल है, जो केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य और श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप है।

दिशा-निर्देशों में अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में निर्धारित गिरफ्तारी सुरक्षा उपायों का सख्त अनुपालन, संवेदनशील मामलों में सरकारी अभियोजक से पूर्व कानूनी राय और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 176(1) के तहत बेतुकी या राजनीति से प्रेरित शिकायतों को बंद करना अनिवार्य किया गया है।

उच्चतम न्यायालय में तेलंगाना राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने प्राथमिकी रद्द करने को चुनौती नहीं दी, लेकिन दिशा-निर्देशों के दायरे पर आपत्ति जतायी और कहा कि वे एक जैसी नहीं हैं। उनमें सुधार की जरूरत है। उच्चतम न्यायालय ने हालांकि इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि वह उच्च न्यायालय के दिये गये निर्णय या तैयार किये गये दिशा-निर्देशों में हस्तक्षेप का इच्छुक नहीं है।

बेटी की शादी करने आयी महिला का खोया हुआ बैग बरामद कर लौटाया

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

हरियाणा से बेटी की शादी करने के लिए हरिद्वार आयी एक महिला का बैग रिक्शा में छूट गया। बैग में कपड़ों के अलावा करीब दो लाख रुपये नकद भी रखे हुए थे। पुलिस ने महिला की सूचना पर ई रिक्शा को ढूंढकर उसका बैग बरामद कर वापस लौटाया।

पुलिस के मुताबिक 03 जनवरी को एक महिला निवासी बडा बाजार रोहतक हरियाणा ने कोतवाली ज्वालापुर पर आकर सूचना दी कि वह अपनी बेटी की शादी कराने होटल मधुबन रानीपुर ज्वालापुर हरिद्वार आयी। बस अड्डा से ई-रिक्शा में बैठकर रानीपुर मोड आयी तो ई-रिक्शा से उतरते वक्त उसका बैग उसी रिक्शा में छूट गया। बैग में उसने अपनी बेटी की शादी के लिए करीब 2 लाख रुपये रखे हुए थे। महिला को ई-रिक्शा का नम्बर व रिक्शा चालक का नाम पता कुछ भी पता नही था। सूचना प्राप्त होने पर प्रभारी निरीक्षक ज्वालापुर द्वारा एसएसआई खेमेन्द्र गंगवार के नेतृत्व में टीम का गठन कर उक्त महिला के बैग की तलाश/जाँच शुरु कर दी। गठित टीम को घनी आबादी क्षेत्र ज्वालापुर में बिना नम्बर की जानकारी व चालक का नाम पता अज्ञात ई-रिक्शा की तलाश किया जाना किसी चैलेंज से कम नहीं था क्योंकि वर्तमान में हरिद्वार क्षेत्र में कई ई-रिक्शा चल रहे हैं। ज्वालापुर पुलिस टीम द्वारा कडी मेहनत व सुरागरसी पतारसी तथा सीसीटीवी कैमरो की मदद से तथा थाना क्षेत्र तथा जनपद हरिद्वार में पडने वाले विभिन्न ई-रिक्शा स्टैण्ड व बस स्टैण्ड में ई-रिक्शा चालक को तलाश किया गया। पुलिस की यह मेहनत रंग लायी और गुरूवार को सीसीटीवी कैमरे की मदद से ई-रिक्शा को तलाश किया गया। जिसके पास से महिला का बैग बरामद किया गया। ई-रिक्शा चालक द्वारा बताया गया कि वह महिला की तलाश कर रहा था ताकि उसका खोया हुआ बैग उसे लौटा संकू। ज्वालापुर पुलिस टीम द्वारा बरामद बैग को महिला के सामने खोला गया तो बैग से 02 लाख 16 हजार रुपये नगद मिले। जिसके बारे में महिला ने बताया कि यह वही पैसे हैं जो उसने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे थे। ज्वालापुर पुलिस की तत्पर्ता व मेहनत तथा सीसीटीवी कैमरों की मदद से महिला के खोये गये बैग व पैसो को बरामद कर महिला के सुपुर्द किया गया। महिला द्वारा हरिद्वार पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित: सरकार

नयी दिल्ली। सरकार ने समग्र शासन व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका की स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए गुरुवार को राज्य सभा में कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की तर्ज पर एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के प्रस्ताव पर विचार हुआ है और यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित है। विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान अपने मंत्रालय से जुड़े सवालों पर सदस्यों के अनुपूरक प्रश्नों के जवाब देते हुए कहा कि आईएएस आईपीए की तरह न्यायाधीशों की भर्ती के लिए एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की व्यवस्था पर अनुच्छेद 312 के तहत सरकार को किसी अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार है। मेघवाल ने कहा कि इस विषय पर न्यायाधीशों के सम्मेलन में भी चर्चा हो चुकी है। इस पर राज्यों के उच्च न्यायालयों की भी राय ली गयी है। मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है और यह अभी 'लंबित है।'

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जैसे प्रस्ताव पर पुनर्विचार की योजना के बारे में विधि एवं न्याय राज्य मंत्री ने कहा कि जैसा कि सभी जानते हैं कि इस तरह के पारित कानून को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था। उसके बाद ऐसी नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया संबंधी ज्ञापन (मेमोरेंडा ऑफ प्रासेस) को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। इसके तय होने के बाद आगे के कदम के बारे में विचार किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के राजीव शुक्ल के जिलास्तरीय न्यायपालिका में रिक्तियों और लंबित मामलों के बोझ के एक सवाल पर कहा कि इनकी भर्तियों के लिए 16 राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोगों और बाकी जगहों पर 13 उच्च न्यायालयों द्वारा भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा 7 साल के अनुभव वाले अधिवक्ता को भी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में चुना जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जिला और सत्र न्यायालयों में स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाई है। 2027 में जिलास्तरीय अदालतों में कुल स्वीकृत पद 19518 थे जिनमें 9300 से भी अधिक की वृद्धि कर इन्हें 25893 कर दिया गया है। उन्होंने कहा जिलास्तरीय न्यायपालिका में नियुक्ति की परीक्षाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों और महिलाओं की भर्तियां भी हो रही हैं। उन्होंने कहा, 'महिलाएं अब बड़ी संख्या में आ रही है। एक राज्य में एक परीक्षा में सफल महिलाओं का अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक था।'

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने की स्वरोजगार परक योजनाओं की समीक्षा, लक्ष्य पूर्ति के दिये निर्देश

पथ प्रवाह, पौड़ी। विभिन्न स्वरोजगार परक योजनाओं के तहत गठित जिला प्राधिकृत समिति, जिला स्तरीय समीक्षा समिति तथा जिला स्वरोजगार प्रोत्साहन एवं अनुश्रवण समिति की संयुक्त बैठक जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय समीक्षा समिति के अंतर्गत सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिये कि लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति की अद्यतन सूचना प्रस्तुत की जाए तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का फॉलोअप करते हुए एक पखवाड़े के भीतर

निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। डेयरी विभाग को गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना के अंतर्गत बैंक स्तर पर लंबित आवेदनों को एक सप्ताह में निस्तारित कराने तथा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के लक्ष्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। कृषि विभाग को कृषि यंत्रीकरण के 40 लक्ष्यों को माह के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिये गये। जिला प्राधिकृत समिति की बैठक में उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन के तहत प्राप्त 10 आवेदनों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये गये। ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे से संबंधित नक्शा प्रकरणों को पर्यटन अधिकारी एवं एएमए जिला पंचायत को आपसी समन्वय से निस्तारित करने को कहा गया, ताकि स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल सके।

जिला स्वरोजगार प्रोत्साहन एवं अनुश्रवण समिति के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत लक्षित 725 इकाइयों का लक्ष्य पूर्ण करने, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे विकास योजना के 20 लक्ष्यों को समय पर पूरा करने तथा उद्यान विभाग की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के 40 लक्ष्यों को प्राप्त करने के निर्देश दिये गये। पशुपालन विभाग को बकरी पालन एवं गौपालन योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिये गये।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, प्रबंधक उद्योग राजेन्द्र आर्या, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी एन.के. ओझा, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी डॉ. विशाल शर्मा, जिला पर्यटन एवं विकास अधिकारी खुशाल सिंह नेगी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

एक नजर

कोटद्वार प्रकरण: मोहम्मद दीपक पर लगाया कांग्रेस का एजेंट होने का आरोप

पथ प्रवाह, हरिद्वार। कोटद्वार प्रकरण को लेकर गुरूवार को प्रेस क्लब हरिद्वार में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में दर्जनों सामाजिक संगठनों ने मोहम्मद दीपक पर कांग्रेस का एजेंट होने का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस पर प्रदेश का माहौल खराब करने और तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। सामाजिक संगठनों ने ऐलान किया कि 14 फरवरी को कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। प्रेस वार्ता में प्रजापति राष्ट्रीय प्रजापति मंच की संगीता प्रजापति, अंबेडकर महामंच के प्रवीण पेंगवाल, भैरव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहित चौहान, बजरंग दल के जिला संयोजक अमित मुल्तानिया, दलित आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीनेश्वर सहित कई संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि मोहम्मद दीपक कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहा है और उसके माध्यम से प्रदेश में सामाजिक तनाव फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। भैरव सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहित चौहान ने कहा कि कोटद्वार प्रकरण से यह स्पष्ट हो गया है कि मोहम्मद दीपक कांग्रेस का एजेंट है, जिसका सर्व समाज विरोध करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और भीम आर्मी मिलकर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मोहम्मद दीपक को राष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और हिंदू विरोधी ताकतें खुलकर उसके समर्थन में सामने आ रही हैं। दलित आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीनेश्वर ने कहा कि जब नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं होती हैं, तब ऐसे लोग गायब रहते हैं, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे प्रकरणों को हवा दी जाती है। प्रजापति राष्ट्रीय प्रजापति मंच की संगीता प्रजापति ने कहा कि पुलवामा जैसे हमलों में जब धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या की जाती है, तब ऐसे तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता चुप रहते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि किसी बाबा के नाम पर स्थानीय हिंदू समाज को आपत्ति थी, तो मारपीट करने का अधिकार किसने दिया।

बजरंग दल के जिला संयोजक अमित मुल्तानिया ने कहा कि यह मामला देश के युवाओं की सोच पर सीधा हमला है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद विरोधी मानसिकता के लोग एक मंच पर आकर दीपक मोहम्मद प्रकरण को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। सभी संगठनों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि 14 फरवरी को कांग्रेस मुख्यालय का घेराव कर विरोध दर्ज कराया जाएगा।

हाउसिंग सोसायटी में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, लाठी-डंडों चले, दो घायल

पथ प्रवाह, हरिद्वार। बहादराबाद थाना क्षेत्र में हाईवे पर स्थित आरोग्यम हाउसिंग सोसायटी उस समय रणक्षेत्र में तब्दील हो गई, जब सोसायटी की वर्किंग कमेटी और सिक्योरिटी ठेके को लेकर चल रहा विवाद अचानक हिंसक संघर्ष में बदल गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और लाठी-डंडों से जमकर एक-दूसरे पर हमला किया, जिससे सोसायटी परिसर में अफरा-तफरी मच गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पहले तीखी नोक-झोंक हुई, जो कुछ ही मिनटों में मारपीट में बदल गई। झगड़े के दौरान लाठियों के प्रहार से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह दोनों पक्ष एक-दूसरे पर लाठियों से हमला कर रहे हैं, जबकि आसपास मौजूद लोग दहशत में इधर-उधर भागते नजर आ रहे हैं। वीडियो के वायरल होते ही मामला चर्चा का विषय बन गया है।

सूचना मिलते ही बहादराबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और इलाके में शांति व्यवस्था बहाल की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला सोसायटी के आंतरिक प्रबंधन और सिक्योरिटी ठेके को लेकर उपजे विवाद से जुड़ा सामने आया है।

बीपीएड पैठाणी ने जीती स्वर्गीय विपिन सिंह एवं स्वर्गीय प्रताप सिंह राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता

पथ प्रवाह, पौड़ी।

पाबौ के खूंडेश्वर खेल मैदान में आयोजित स्वर्गीय विपिन सिंह एवं स्वर्गीय प्रताप सिंह राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का ओपन वर्ग फाइनल मुकाबला खेल प्रेमियों के लिए बेहद रोमांचक रहा। तेज रफ्तार खेल, सधी हुई रणनीति और खिलाड़ियों की अथक मेहनत ने पूरे मैदान को जोश और उत्साह से भर दिया। दर्शकों ने हर शानदार पास, टैकल और गोल प्रयास पर तालियों की गूंज से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया।

फाइनल मुकाबला बीपीएड पैठाणी और 12वीं गढ़वाल के बीच खेला गया। दोनों ही टीमों ने शुरुआत से आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन मजबूत डिफेंस और चौकस गोलकीपरों के चलते मध्यांतर तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। दूसरे हाफ में भी मुकाबला बराबरी का बना रहा और दोनों टीमों को कई सुनहरे मौके मिले, लेकिन गोल का इंतजार बना रहा। मैच समाप्त होने से कुछ ही समय पहले बीपीएड पैठाणी के पंकज छेत्री ने शानदार गोल दागकर अपनी टीम को 1-0 की निर्णायक बढ़त दिला दी। अंतिम क्षणों में 12वीं गढ़वाल ने बराबरी की भरपूर कोशिश की, लेकिन बीपीएड पैठाणी की मजबूत रक्षा पंक्ति के आगे उनकी एक न चली।

विजेता बीपीएड पैठाणी टीम को मुख्य

अतिथि राजकीय महाविद्यालय पैठाणी के प्राचार्य डॉ. जितेंद्र नेगी, समिति अध्यक्ष कर्मवीर भंडारी, समिति संरक्षक दुर्गेश प्रसाद एवं जिला पंचायत सदस्य भारत रावत द्वारा 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। मैच के हीरो पंकज छेत्री को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया। उपविजेता 12वीं गढ़वाल टीम को 51 हजार रुपये की धनराशि और ट्रॉफी प्रदान की गई।

अंडर-16 वर्ग के फाइनल में छानी की टीम ने पौड़ी एफसी को हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया। वहीं रस्साकसी प्रतियोगिता में कोटली की महिला टीम ने कोटा को पराजित कर विजेता बनने का गौरव हासिल किया। विजेता टीम को 11,000 रुपये और उपविजेता को 5,100 रुपये की राशि दी गई। मैच की कमेंट्री मातवर सिंह चौहान और सुधीर रावत ने की, जबकि फेसबुक लाइव प्रसारण हरेंद्र कोहली द्वारा किया गया।

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

पथ प्रवाह, नैनीताल।

जनपद नैनीताल में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। भवाली पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने इस प्रकरण पर स्पष्ट संदेश दिया है कि ऐसे जघन्य अपराधों में किसी भी स्तर पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी और आरोपी की संपत्ति के विरुद्ध भी जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

04 फरवरी 2026 को कोतवाली भवाली को सीएचसी अस्पताल भवाली से सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग युवती छह माह की गर्भवती है। सूचना मिलते ही भवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीड़िता के परिजनों से संपर्क किया। पीड़िता की माता की तहरीर के आधार पर थाना भवाली में मु0अ0सं0 04/26 अंतर्गत धारा 64 बीएनएस एवं 5(ज)/11/6 पोक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें आरोपी का नाम साहिल दर्ज किया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी. ने

तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. जगदीश चंद्रा एवं अधीनस्थ पुलिस टीम को दिए। निर्देशों के क्रम में पुलिस टीम ने संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ दबिश दी और 05 फरवरी 2026 को दुष्कर्म के अभियुक्त साहिल को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त का फॉरेंसिक लैब टीम द्वारा परीक्षण, मेडिकल परीक्षण तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई। इसके बाद अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी. ने कहा कि पुलिस पूरी संवेदनशीलता और सख्ती के साथ वैधानिक कार्रवाई कर रही है। क्षेत्र में माहौल खराब करने का प्रयास करने वालों पर नैनीताल पुलिस की मॉनिटरिंग सेल सतत निगरानी रखे हुए है और ऐसे तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

पुलिस टीमः

वरि0 उ0नि0 आसिफ खान, म0उ0नि0 गुरविंदर कौर, उ0नि0 रमेश पंत, उ0नि0 मनोज अधिकारी, हे0कानि0 लालबाबू, कानि0 हरीश सिंह, कानि0 भुवन कापड़ी

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने जांची परखी चारधाम यात्रा व्यवस्था की तैयारी, दिए निर्देश

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी

उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। आगामी चारधाम यात्रा को सुचारु, सुरक्षित एवं व्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी प्रशांत आर्य द्वारा ने यमुनोत्री धाम चारधाम यात्रा से संबंधित प्रमुख मार्गों, पड़ावों एवं व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने यात्रा मार्गों की स्थिति, पैदल मार्ग, सड़क सुरक्षा, यात्री सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन, पार्किंग स्थलों, आवासीय व्यवस्थाओं एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कर ली जाएं।

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने एनएच, लोनिवि, जल संस्थान और विद्युत विभाग के अधिकारियों को यात्रा रूट पर निर्बाध सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने पैदल मार्ग पर संवेदनशील स्थानों का चिन्हीकरण कर वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने तथा घोड़े-खच्चरों के लिए गर्म पानी व पड़ावों पर स्वच्छता की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सुरक्षात्मक कार्यों में गुणवत्ता की किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग को यात्रा मार्गों एवं प्रमुख पड़ावों पर मेडिकल राहत पोस्ट, एंबुलेंस, आवश्यक दवाइयों एवं चिकित्सकीय स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अधिशासी अभियंता यूपीसीएल को स्यानाचट्टी, रानाचट्टी, हनुमान चट्टी, जानकीचट्टी और मंदिर परिसर में स्ट्रीट लाइट्स और पोल सहित निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। पालीगाड़ बाजार में जल भराव की समस्या के निराकरण के लिए चल रहे सीसी कार्य को मार्च से पहले पूरा करने और अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अधिशासी अभियंता एनएच को अवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। औजरी पुल के मरम्मत कार्य शुरू होने से पूर्व वैकल्पिक पैच मार्ग तैयार कर आवागमन सुचारु रखें। डाबरकोट भूस्खलन जोन सहित अन्य भूस्खलन ट्रीटमेंट कार्यों में तेज़ी लाई जाए तथा डंपिंग जोन को व्यवस्थित तरीके से उपयोग करें ताकि यात्रा के दौरान कोई अव्यवस्था ना हो। रानाचट्टी में सड़क चौड़ीकरण के दौरान बीच में आ रहे पोल के युटिलिटी शिफ्टिंग के लिए एनएच और विद्युत विभाग को समन्वय स्थापित कर शिफ्टिंग का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिये।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने हलना-कुथनौर सड़क मार्ग की संवेदनशीलता को देखते हुए अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई को रिटेनिंग वॉल निर्माण का कार्य तत्काल शुरू करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कार्यदायी संस्था को स्पष्ट किया कि यात्रा सीजन और स्थानीय आवाजाही के मद्देनजर सुरक्षा कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने लोनिवि गेस्ट हाउस जानकीचट्टी में यमुनोत्री यात्रा से संबंधित अधिकारियों और हितधारकों के साथ बैठक ली। इस दौरान यात्रा को लेकर जिलापंचायत की तैयारियों की जानकारी ली तथा शौचालय और साफ-सफाई की व्यवस्थाएं सुनिश्चित रखने के निर्देश दिये। उन्होंने मंदिर समिति एवं स्थानीय हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित कर यात्रा को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने की बात कही।

अधिशासी अभियंता लोनिवि को यात्रा रूट पर साइनेज और सौंदर्यकरण संबंधित सभी कार्य करने और हेलीपैड के सड़क पैच को जिला योजना में रखने के निर्देश दिये। खरसाली पुल से खरसाली मंदिर तक की सड़क को लोनिवि को हस्तांतरित करने के लिए के लिए उपजिलाधिकारी, ब्रिडकुल और लोनिवि को संयुक्त टीम बनाकर सोमवार तक निरीक्षण करके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। प्लास्टिक कचरे को यमुना नदी में गिरने से रोकने के लिए लोनिवि को पैदल यात्रा मार्ग पर नेट जाली लगाने के निर्देश दिये।

जिलाधिकारी ने कहा कि चारधाम यात्रा प्रदेश एवं जनपद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा एवं स्वास्थ्य प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

इस दौरान जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्यानाचट्टी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारी को बच्चों के स्कूल जाने वाले रस्ते का निर्माण करने के निर्देश दिए ताकि स्कूली बच्चों को आवाजाही में समस्या ना हो। बच्चों से अध्यापन सम्बंधित स्थिति भी जांची तथा अधिशासी अभियंता जल संस्थान को स्कूल के अंदर पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

निरीक्षण के दौरान पर उप जिलाधिकारी मुकेश रमोला,अधिशासी अभियंता जल संस्थान विनोद पांडे,अधिशासी अभियंता एनएच मनोज रावत, अधिशासी अभियंता यूपीसीएल धर्मवीर सिंह, अधिशासी अभियंता लोनिवि तरुण कंबोज , प्रभारी निरीक्षक थाना बड़कोट सुभाष चंद एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

वनाग्नि की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने ली बैठक, समन्वय व सतर्कता बनाने के दिये निर्देश

पथ प्रवाह, पौड़ी।

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में वनाग्नि रोकथाम को लेकर बैठक लेते हुए सभी विभागों को समन्वित, सक्रिय और ज़मीनी स्तर पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि समय से पूर्व की गई तैयारी ही वनाग्नि से होने वाली क्षति को न्यूनतम कर सकती है तथा इसमें जनसहभागिता की अहम भूमिका है।

जिलाधिकारी ने वन विभाग को निर्देश दिये कि वनाग्नि के सभी संभावित कारणों को ध्यान में रखते हुए जनपद स्तर से ग्राम स्तर तक बनी समितियों को सक्रिय रखा जाए। आग की घटनाओं की रोकथाम हेतु उपलब्ध उपकरणों की समुचित जाँच, मानव संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता तथा फायर वाचरों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि आग लगाते हुए पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाए। साथ ही सभी वन प्रभागों में वनाग्नि की सूचनाओं के आदान -प्रदान हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना कर उनका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए तथा आपात स्थिति में त्वरित सूचना तंत्र को प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने जिला मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों संस्थानों के अधिकारियों को निर्देश दिये सभी अधिकारी अपने-अपने कार्यालय के आसपास घास-फूस, कूडा करकट व झाडियों की नियमित सफाई बनाये रखें। वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये वनाग्नि की दृष्टि से संवेदनशीन और अतिसंवेदनशील स्थलों के आसपास की बसावटों यथा गांवों, कसबों की मैपिंग प्राथमिकता के अधार पर करवाना सुनिश्चित करें। उन्होने युवा कल्याण अधिकारी को निर्देश दिये कि ग्राम स्तर पर बने सभी युवा एवं महिला मंगल दलों व ग्राम प्रहरियों को सक्रिय रखें।

बैठक में बताया गया कि जनपद का 61.38 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। वनाग्नि का सर्वाधिक खतरा 15 फरवरी से 15 जून के मध्य रहता है। जनपद में 5795.50 हेक्टेयर क्षेत्र अति संवेदनशील तथा 70717 हेक्टेयर क्षेत्र संवेदनशील श्रेणी में है। वर्तमान में 260 क्रू स्टेशन स्थापित किये गए हैं। प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी वन प्रभाग महातिम यादव ने बताया कि वनाग्नि रोकथाम के दृष्टिगत जनपद में कुल 09 कंट्रोल रूम स्थापित किये गये हैं। पर्याप्त संख्या में क्रू स्टेशनों की स्थापना की जा चुकी है तथा फायर वाचरों की तैनाती की प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि ग्राउण्ड लेवल पर मॉक ड्रिल, शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके अलावा वन अग्नि रोकथाम के क्रम में लीसा विदोहन की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।

बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. शिवमोहन शुक्ला, अधीक्षण अभियंता जल संस्थान प्रवीण सैनी, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी रविन्द्र फोनिया सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

एचईसी कॉलेज में नाटक मंचन कर दर्शायी विभाजन के समय महिलाओं की स्थिति

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

एचईसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स, हरिद्वार में कला एवं मानविकी विभाग द्वारा 'देश विभाजन में महिलाओं की स्थिति' पर एक नाटिका का आयोजन किया गया, जिसका शीर्षक था 'विभाजन एवं महिलाएं:अनसुना दर्दः। इस नाटिका के माध्यम से देश विभाजन के समय महिलाओं द्वारा सहन किये गये मानसिक एवं शारीरिक दर्द को दिखाया गया है। इस नाटिका में सोनाक्षी, कशिश, रिति, अराध्या, दीपक, वंश, लक्ष्य चौहान, लक्ष्य भट्ट, गरीमा, प्रगति, खुशबु, स्नेहा एवं नियति ने प्रतिभाग किया।

इस नाटिका का संयोजन डॉ. करूणा नेहरा के निर्देशन में सम्पन्न हुआ। संस्थान की प्राचार्या डॉ. तृप्ति अग्रवाल ने नाटिका के प्रतिभगियों की सराहना करते हुए कहा कि इन नाटकों के माध्यम से हम अपने इतिहास से परिचित होते हैं। इस आयोजन में छात्रों के साथ विभागाध्यक्ष डॉ. तनु चन्द्रा, सुनीति त्यागी, वन्दना सैनी, स्वाति मंगलम, दीपाली, योगराज सिंह, वीरेन्द्र आदि शिक्षकगण उपस्थित रहे।

फरसूला में लगे बहुउद्देश्यीय शिविर में दर्ज हुई 78 शिकायतें, 122 लोगों को मिला योजनाओं का लाभ

पथ प्रवाह, पौड़ी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन पर जनपद की सभी न्याय पंचायतों में चलाए जा रहे जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान के तहत विकासखंड दुगड्डा की न्याय पंचायत फरसूला में बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 522 लोगों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान 78 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं 122 लोगों को विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ दिया गया। शिविर की अध्यक्षता पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय ने की। उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल से आम जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने स्थानीय लोगों को कहा कि अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ लें। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविरों के माध्यम से समस्याओं का समाधान और योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। पीडी डीआरडीए ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में दर्ज शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन शिकायतों का समाधान मौके पर नहीं हो पाया है उनका शीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करें। शिविर में 23 विभागों के स्टॉल लगाए गए थे। विभागीय स्टॉलों के माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही लाभ प्रदान किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख सूरज नेगी, ज्येष्ठ प्रमुख सुनील कुमार, अधिशासी अभियंता जल निगम आशीष मिश्रा, खंड विकास अधिकारी विद्यादत्त रतूड़ी, ग्राम प्रधान रेखा देवी, किरण देवी, विनोद, प्रभा देवी सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग उपस्थित थे।

स्वामी/प्रकाशक वीरेन्द्र सिंह ने मुद्रक प्रमोद कुमार, जय माँ गंगा प्रिन्टर्स, राजराणा कॉम्पलैक्स निकट खाद गोदाम, जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से मुद्रित कराकर, मुख्य कार्यालयः 40 शांतिपुरम कॉलोनी जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड 249408 (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया। वीरेन्द्र सिंह (सम्पादक) 9411111733, डॉ सुशील शर्मा(उप संपादक) 9837906777 किसी भी वाद विवाद का निपटारा हरिद्वार में होगा। वेबसाईट- www.pathpravah.com